भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 361

15 सितम्बर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती को बढ़ावा देना

361. श्री कृष्ण पाल सिंह यादवः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए कोई विशेष योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई-सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में केन्द्रीय योजना) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनइआर-पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना) नामक समर्पित योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। दोनों योजनाओं का लक्ष्य रसायन मुक्त, कम आदान लागत, सतत् जैविक खेती पर कलस्टर को बढ़ावा देना है और किसानों की आदान खरीद को मंडी संपर्कों तक सहायता करना है।

जैविक खेती को अन्य योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत जैविक खेती नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत भी सहायता प्रदान की जाती है। कृषि प्रसंस्कृत खाद्य एवं निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा), वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जैविक खेती के तृतीय पक्ष प्रमाणन को बढ़ावा दिया जाता है।

(ख) से (घ): योजना में पैकेजिंग, जैविक उत्पादों के विपणन सहित मूल्य संवर्धन को बढ़ाना अंतर्निहित है। योजना के तहत जैविक मेलों, क्रेता-विक्रेता प्रतियोगिताओं, जैविक स्टोरों के निर्माण आदि को भी सहायता दी जाती है। कुछ प्रमुख निर्यातकों/कृषि-व्यापार, पादप रसायन के साथ एफपीओ/उत्पादक कलस्टरों से मंडी संपर्क और ऑनलाईन किराना स्टोर स्थापित किए गए हैं।

जैविक खेती ई-कॉमर्स पोर्टल, https://www.jaivikkaeti.in, बनाया गया है। यह पोर्टल जैविक खेती में शामिल क्षेत्रीय परिषदों, स्थानीय समूहों, व्यैक्तिक, किसानों, क्रेताओं, सरकारी एजेंसियों जैसे विभिन्न हितधारकों को जोड़ता है। इसमें जैविक उत्पाद के विपणन को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम नीलामी, मूल्य मात्रा बोली, बुक-बिल्डिंग, तथा रिवर्स नीलामी तंत्रों जैसे विभिन्न मूल्य प्राप्ति तंत्र भी है। पोर्टल पर 3.47 लाख किसान पंजीकृत है।

****